

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और कौशल शिक्षा: स्वदेशी आंदोलन से
आत्मनिर्भर भारत तक
**Indian Freedom Movement and Skill Education: From the Swadeshi Movement
to Atmanirbhar Bharat**

विपिन सहरावत

Vipin Sehrawat

Assistant Professor (History),
Shri Vishwakarma Skill University, Haryana

vipinsehrawat108@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.22860541>

सारांश

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई ही नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आत्मनिर्भरता की एक सशक्त ऐतिहासिक प्रक्रिया भी थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शासन ने भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, हस्तशिल्प और कौशल-आधारित उद्योगों को योजनाबद्ध रूप से कमजोर किया, जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी कौशल और कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। इसके प्रतिरोध में 1905 का स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने स्थानीय उत्पादन, तकनीकी शिक्षा और पारंपरिक कौशलों के पुनर्जीवन की दिशा भी निर्धारित की।

महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन (नई तालीम) के माध्यम से शिक्षा और उत्पादन के बीच गहरे संबंध को स्थापित किया। उनका उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना था जो केवल साक्षर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल से युक्त होकर आत्मनिर्भर बन सकें। स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में कौशल शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण की आधारशिला के रूप में देखा गया, जिसका प्रभाव स्वतंत्र भारत की शैक्षिक नीतियों और पंचवर्षीय योजनाओं पर भी पड़ा।

वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत पुनः उसी ऐतिहासिक पथ पर अग्रसर दिखाई देता है। यह अध्ययन गुणात्मक ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक कौशल नीतियाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक विरासत का ही आधुनिक विस्तार हैं।

Abstract

The Indian freedom movement was not merely a political struggle against colonial rule but also a comprehensive movement aimed at achieving social, economic and educational self-reliance. British colonial policies severely undermined India's traditional systems of skill education, indigenous industries, and handicrafts, leading to widespread economic dependency and unemployment among artisan communities. In response, the Swadeshi Movement of 1905 emerged as a powerful expression of resistance that emphasized the boycott of foreign goods and the revival of indigenous skills and local industries.

Mahatma Gandhi further strengthened this vision through his concept of Basic Education (Nai Talim), which sought to integrate education with productive labour and vocational skills. Throughout

the freedom struggle, skill education was viewed as a foundation for nation-building and self-sufficiency. This qualitative historical study analyzes the continuity of skill education from the Swadeshi Movement and Gandhian educational thought to contemporary initiatives such as Skill India, Atmanirbhar Bharat, and the National Education Policy 2020. The paper argues that modern skill-development policies represent an extension of the historical legacy of the freedom movement and reaffirm the centrality of skill education in India's nation-building process.

मुख्य शब्द: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, कौशल शिक्षा, नई तालीम, आत्मनिर्भर भारत

Key words: Indian Freedom Movement, Swadeshi Movement, Skill Education, Nai Talim, Atmanirbhar Bharat

परिचय

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता को समाप्त करने का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का भी एक व्यापक अभियान था। औपनिवेशिक शासन ने भारत की पारंपरिक उत्पादन प्रणाली, शिल्पकला और शिक्षा व्यवस्था को जिस प्रकार प्रभावित किया, उसने भारतीय समाज को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरे आघात पहुँचाए। भारत का वस्त्र उद्योग, जो कभी विश्व बाजारों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था, ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों और व्यापारिक हितों के कारण लगभग नष्ट हो गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय हस्तशिल्प और कारीगर वर्ग बेरोजगारी, निर्धनता और सामाजिक हाशिये की स्थिति में पहुँच गया।

औपनिवेशिक शासन की शिक्षा नीति ने भी भारतीय समाज की आत्मनिर्भरता को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा को श्रम, उत्पादन और कौशल से अलग कर दिया गया, जिससे भारतीय युवाओं में शारीरिक श्रम और व्यावहारिक कार्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी स्थायी और सार्थक होगी जब समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और शिक्षा कौशल तथा उत्पादन से जुड़ी होगी। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन, नई तालीम और कौशल शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण के अनिवार्य उपकरण के रूप में देखा गया।

औपनिवेशिक शिक्षा नीति और कौशल का ह्रास

भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन के लिए आवश्यक लिपिक, सहायक और निम्नस्तरीय अधिकारी तैयार करना था। 1835 के मैकॉले मिनट ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पश्चिमी ढाँचे में ढालने का प्रयास किया। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा और साहित्य को श्रेष्ठ ज्ञान का माध्यम घोषित किया गया, जबकि भारतीय पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और कौशल-आधारित शिक्षा को हीन और अप्रासंगिक माना गया। 1854 का वुड्स डिस्पैच यद्यपि शिक्षा के विस्तार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, परंतु इसमें भी औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा को सीमित और गौण स्थान ही प्राप्त हुआ। शिक्षा का उद्देश्य समाज को आत्मनिर्भर बनाना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। परिणामस्वरूप भारतीय युवाओं को इस प्रकार शिक्षित किया गया कि वे उत्पादनकर्ता बनने के बजाय उपभोक्ता और कर्मचारी बनकर रह गए।

इस शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय समाज की मानसिकता पर पड़ा। श्रम और कौशल को निम्न श्रेणी का कार्य माना जाने लगा, जबकि कार्यालयीन कार्य और सरकारी सेवा को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा गया। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यवसाय धीरे-धीरे उपेक्षित होते चले गए। औपनिवेशिक व्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और विदेशी निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता के रूप में सीमित कर दिया। इस प्रक्रिया ने भारत की आत्मनिर्भरता को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त

किया। इतिहासकारों ने इस स्थिति को 'औपनिवेशिक निर्भरता की संरचना' के रूप में देखा, जिसमें शिक्षा और कौशल दोनों को औपनिवेशिक हितों के अनुरूप ढाला गया। यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिक्षा सुधार और कौशल पुनरुद्धार को राजनीतिक संघर्ष से अलग नहीं माना गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने यह समझ लिया था कि बिना कौशल-आधारित शिक्षा के स्वतंत्र भारत की कल्पना अधूरी रहेगी।

स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता की चेतना

1905 में बंग-भंग के विरोध में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। यह आंदोलन केवल एक तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक वर्चस्व के विरुद्ध एक व्यापक वैचारिक प्रतिरोध था। स्वदेशी आंदोलन का मूल स्वर था—विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादन को अपनाना। इस आह्वान के पीछे यह गहरी समझ निहित थी कि औपनिवेशिक शासन भारत को आर्थिक रूप से निर्बल बनाकर राजनीतिक रूप से नियंत्रित करना चाहता था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाना केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज को अपने पारंपरिक कौशल, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों की ओर पुनः उन्मुख करने का प्रयास था। वस्त्र उद्योग इसका सबसे सशक्त उदाहरण था। जहाँ ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग लगभग नष्ट हो चुका था, वहीं स्वदेशी आंदोलन ने चरखा, खादी और कुटीर उद्योगों को राष्ट्रीय आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित किया। इस प्रक्रिया में कौशल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को पुनर्जीवित करने की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने आर्थिक प्रतिरोध को शैक्षिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से जोड़ा। आंदोलन के दौरान अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के विकल्प के रूप में कार्य करना था। कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज और

बंगाल टेक्निकल इंस्टिट्यूट जैसे संस्थानों की स्थापना इसी भावना का परिणाम थी। इन संस्थानों में छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि तकनीकी, व्यावहारिक और कौशल-आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इन राष्ट्रीय संस्थानों की शिक्षा पद्धति इस विचार पर आधारित थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी के लिए योग्य बनाना नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना हो। यहाँ छात्रों को विज्ञान, तकनीक और हस्तशिल्प के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ा गया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन ने शिक्षा और कौशल को राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष का अभिन्न अंग बना दिया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध निबंध 'स्वदेशी समाज' में यह स्पष्ट किया कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब समाज अपने श्रम, संसाधनों और रचनात्मक क्षमता पर आधारित हो। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से राष्ट्र सशक्त नहीं बन सकता, जब तक कि सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित न हो। शांति निकेतन की स्थापना इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में हुई, जहाँ शिक्षा को प्रकृति, संस्कृति और श्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ कला, शिल्प, कृषि और रचनात्मक कार्य शिक्षा का अनिवार्य अंग थे।

स्वदेशी आंदोलन ने इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया कि कौशल शिक्षा केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक पुनरुत्थान का साधन भी है। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय समाज में श्रम के प्रति सम्मान और स्थानीय उत्पादन के प्रति गर्व की भावना का विकास हुआ। यह चेतना आगे चलकर गांधीजी की नई तालीम और स्वतंत्रता के बाद की शैक्षिक नीतियों की वैचारिक नींव बनी।

गांधीजी की दृष्टि और 'नई तालीम'

महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का साधन नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पुनर्निर्माण की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके लिए स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ आत्मनिर्भरता था—व्यक्ति

की भी और समाज की भी। इस संदर्भ में शिक्षा गांधीजी की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण साधन थी, क्योंकि वही भविष्य के नागरिकों की मानसिकता, मूल्य और व्यवहार का निर्माण करती है।

गांधीजी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उसे परनिर्भर और उपभोक्तावादी बना रही है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को श्रम और उत्पादन से दूर कर दिया तथा उन्हें केवल नौकरी-प्राप्ति तक सीमित कर दिया। इसके विपरीत गांधीजी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, श्रम के प्रति सम्मान विकसित करे और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ी हो।

चरखा और खादी: कौशल व आत्मनिर्भरता के प्रतीक

गांधीजी के चिंतन में चरखा केवल सूत कातने का यंत्र नहीं था, बल्कि वह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक था। खादी उनके लिए केवल वस्त्र नहीं, बल्कि स्वराज और स्वावलंबन की विचारधारा का मूर्त रूप थी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी का प्रयोग एक साथ आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक प्रतिरोध का साधन बन गया। चरखा करोड़ों भारतीयों को रोजगार देने वाला कौशल उपकरण भी था, जिसने उत्पादन को गाँवों और स्थानीय समुदायों से जोड़ा। चरखे के माध्यम से गांधीजी ने यह स्पष्ट किया कि कौशल-आधारित उत्पादन न केवल आर्थिक समस्या का समाधान कर सकता है, बल्कि सामाजिक समानता और आत्मसम्मान का भी आधार बन सकता है। इस प्रक्रिया में शिक्षा, कौशल और नैतिकता एक-दूसरे से अविभाज्य हो जाते हैं।

नई तालीम की अवधारणा

गांधीजी का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक योगदान 'नई तालीम' अथवा 'बेसिक एजुकेशन' की अवधारणा थी। 1937 में प्रस्तुत वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि शिक्षा को श्रम और उत्पादन से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। उनका विश्वास था

कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होना चाहिए। नई तालीम के अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों को बुनाई, कृषि, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, कागज निर्माण, बढईगिरी और ग्रामोद्योग जैसे कार्यों में प्रशिक्षित करने की बात कही गई। गांधीजी का प्रसिद्ध कथन— "सीखते हुए कमाना और कमाते हुए सीखना"— इस शिक्षा पद्धति का मूल आधार था। उनका मानना था कि शिक्षा यदि उत्पादन से जुड़ी होगी तो वह न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि शिक्षा की लागत को भी कम करेगी।

श्रम के प्रति सम्मान और सामाजिक पुनर्निर्माण

नई तालीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में श्रम के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना था। गांधीजी मानते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम के बीच एक कृत्रिम विभाजन पैदा कर दिया है। नई तालीम इस विभाजन को समाप्त करने का प्रयास थी। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार होते थे, जिससे शिक्षा और जीवन के बीच की दूरी कम होती थी। गांधीजी की नई तालीम केवल शैक्षिक प्रयोग नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक दर्शन था। इसका उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना था जो आत्मनिर्भर हों, समाज के प्रति उत्तरदायी हों और राष्ट्रनिर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। यही कारण है कि नई तालीम को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यापक समर्थन मिला और इसे राष्ट्रनिर्माण की आधारशिला के रूप में देखा गया।

नई तालीम की ऐतिहासिक महत्ता

यद्यपि स्वतंत्रता के बाद नई तालीम को शिक्षा नीति में अपेक्षित स्थान नहीं मिला, फिर भी इसके विचार भारतीय शिक्षा विमर्श में लगातार उपस्थित रहे। कौशल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर आज जो बल दिया जा रहा है, उसकी वैचारिक जड़ें गांधीजी की नई तालीम में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इस प्रकार नई तालीम स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐसी विरासत है, जो आधुनिक भारत की कौशल नीतियों में नए रूप में पुनः प्रकट हो रही है।

स्वतंत्रता के बाद कौशल शिक्षा की चुनौतियाँ

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रनिर्माण की थी। इस प्रक्रिया में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का प्रमुख साधन माना गया। किंतु व्यवहार में स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति और कौशल शिक्षा के बीच वह संतुलन स्थापित नहीं हो सका, जिसकी परिकल्पना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की गई थी। गांधीजी की नई तालीम और स्वदेशी आंदोलन की आत्मनिर्भरता की भावना स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा व्यवस्था में धीरे-धीरे हाशिये पर चली गई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित 1948-49 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग) उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता पर केंद्रित था। यद्यपि इस आयोग ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया, परंतु कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक पुनर्निर्माण से जोड़ने का स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया। उच्च शिक्षा का झुकाव मुख्यतः अकादमिक और सैद्धांतिक ज्ञान की ओर रहा। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया, किंतु इसका प्रभाव मुख्यतः इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों तक सीमित रहा। कौशल शिक्षा को व्यापक सामाजिक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि एक सहायक व्यवस्था के रूप में देखा गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 की उसकी पुनरावृत्ति में व्यावसायिक शिक्षा को औपचारिक रूप से स्थान दिया गया, परंतु व्यावहारिक स्तर पर इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ रहीं।

स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण को विकास का प्रमुख मार्ग माना गया। बड़े उद्योगों और भारी मशीनरी पर आधारित विकास मॉडल ने कुटीर उद्योगों और पारंपरिक कौशलों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया। यद्यपि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गई, किंतु उनका दायरा सीमित रहा और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर उन्हें विश्वविद्यालयी शिक्षा के समकक्ष नहीं माना गया। इस असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा और रोजगार के बीच गहरी खाई उत्पन्न हो गई। बड़ी संख्या में

विश्वविद्यालय डिग्रीधारी युवा बेरोजगार रहे, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक और उद्योग-उन्मुख कौशलों का अभाव था। दूसरी ओर उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी का सामना करना पड़ा। यह स्थिति स्वतंत्रता आंदोलन के उस मूल विचार के विपरीत थी, जिसमें शिक्षा को आत्मनिर्भरता और सामाजिक उपयोगिता से जोड़ा गया था। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक यह विडंबना बनी रही कि जिस कौशल शिक्षा और श्रम-आधारित दृष्टिकोण ने स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी थी, वही स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति में गौण बना रहा। गांधीजी की नई तालीम को 'आदर्शवादी' या 'व्यावहारिकता से दूर' कहकर धीरे-धीरे शिक्षा विमर्श से अलग कर दिया गया। परिणामस्वरूप शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर नागरिक निर्माण से हटकर केवल रोजगार-प्राप्ति तक सीमित होता चला गया।

फिर भी, समय-समय पर यह महसूस किया जाता रहा कि बिना कौशल-आधारित शिक्षा के भारत की विशाल जनसंख्या को उत्पादक शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही अंतर्विरोध आगे चलकर इक्कीसवीं सदी में कौशल शिक्षा के पुनर्मूल्यांकन का आधार बना और आधुनिक भारत में स्किल इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का मार्ग प्रशस्त किया।

आधुनिक भारत में कौशल शिक्षा और आत्मनिर्भरता

इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के साथ भारत ने यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि केवल औपचारिक और डिग्री-आधारित शिक्षा देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि ने रोजगार की प्रकृति को बदल दिया। इस परिवर्तित परिदृश्य में कौशल शिक्षा पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई। यह स्थिति किसी नई सोच का परिणाम नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित आत्मनिर्भरता की उसी ऐतिहासिक चेतना का आधुनिक पुनरुत्थान थी।

स्किल इंडिया मिशन और कौशल पुनर्मूल्यांकन

2015 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया स्किल इंडिया मिशन इसी ऐतिहासिक आवश्यकता की

अभिव्यक्ति था। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-अनुकूल, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करना था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों— निर्माण, सेवा, तकनीक, स्वास्थ्य और हस्तशिल्प में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए। यह पहल इस तथ्य की स्वीकारोक्ति थी कि शिक्षा और रोजगार के बीच लंबे समय से बना अंतर कौशल विकास के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। स्किल इंडिया मिशन को यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्वदेशी आंदोलन और गांधीजी की नई तालीम की उसी परंपरा का आधुनिक रूप प्रतीत होता है, जिसमें शिक्षा को उत्पादन, श्रम और आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया था। अंतर केवल इतना है कि जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौशल मुख्यतः कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प तक सीमित थे, वहीं आज कौशल का दायरा तकनीक, डिजिटल साक्षरता और आधुनिक उद्योगों तक विस्तृत हो चुका है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान: स्वदेशी की आधुनिक व्याख्या

2020 में कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया। इस संकट ने भारत को यह पुनः स्मरण कराया कि अत्यधिक बाहरी निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए घातक हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। यह अभियान वस्तुतः स्वदेशी आंदोलन की आधुनिक पुनर्व्याख्या था। 'वोकल फॉर लोकल' का नारा वही विचार दोहराता है, जो एक शताब्दी पूर्व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादन के समर्थन में दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य केवल आत्म-केंद्रित विकास नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पादन को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ऐतिहासिक निरंतरता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा और कौशल के उस ऐतिहासिक संबंध को पुनः स्थापित किया, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की गई थी। इस नीति में विद्यालय स्तर से ही व्यावहारिक कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया गया है। उच्च शिक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए रोजगारपरक और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया है। यह नीति गांधीजी की नई तालीम की मूल भावना से स्पष्ट रूप से मेल खाती है, जिसमें शिक्षा और श्रम को अविभाज्य माना गया था। फर्क केवल इतना है कि आज का श्रम डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक उद्योगों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वतंत्रता आंदोलन की शैक्षिक विरासत का आधुनिक विस्तार कहा जा सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकन

यदि स्वदेशी आंदोलन, नई तालीम और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक निरंतर ऐतिहासिक धारा के रूप में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत की कौशल नीति कोई आकस्मिक प्रयोग नहीं है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित उस वैचारिक आधार का ही परिणाम है, जिसमें आत्मनिर्भरता को राजनीतिक स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त माना गया था। आधुनिक भारत में कौशल शिक्षा इसी ऐतिहासिक सोच को नए संदर्भों और चुनौतियों के अनुरूप पुनः परिभाषित कर रही है।

तुलनात्मक विश्लेषण: स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत तक

नीचे दी गई तालिका पूरे लेख के ऐतिहासिक तर्क को संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। यह तालिका किसी बाहरी आँकड़े पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित है— जो मानविकी शोध के लिए पूर्णतः स्वीकार्य है।

तालिका- 1: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से आधुनिक भारत तक कौशल शिक्षा की ऐतिहासिक निरंतरता

ऐतिहासिक चरण	कौशल शिक्षा का स्वरूप	प्रमुख उद्देश्य	वैचारिक आधार
स्वदेशी आंदोलन (1905)	कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादन	आर्थिक आत्मनिर्भरता	विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी
गांधीजी की नई तालीम (1937)	श्रम-आधारित शिक्षा, ग्रामोद्योग	आत्मनिर्भर नागरिक	श्रम की गरिमा, स्वावलंबन
स्वतंत्र भारत (1950-1990)	ITI, पॉलिटेक्निक	औद्योगिक मानव संसाधन	राज्य-नेतृत्व विकास
स्किल इंडिया (2015)	उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण	रोजगार सृजन	कौशल-रोजगार समन्वय
आत्मनिर्भर भारत (2020)	स्थानीय उत्पादन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा	आर्थिक संप्रभुता	वोकल फॉर लोकल

संभावित अनुप्रयोग

यह अध्ययन न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग भी व्यापक हैं।

प्रथम, यह शोध शिक्षा नीति निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे नीति-निर्माता यह समझ सकें कि कौशल शिक्षा भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक परंपरा का हिस्सा रही है।

द्वितीय, शिक्षक-प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण में यह अध्ययन उपयोगी है, क्योंकि यह शिक्षा को केवल डिग्री-उन्मुख न रखकर रोजगारोन्मुख और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

तृतीय, यह शोध इतिहास और समकालीन नीति के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे विश्वविद्यालयों में अंतर्विषयक (interdisciplinary) अध्ययन को बढ़ावा मिल सकता है।

अंततः, यह अध्ययन युवाओं और शोधकर्ताओं को यह समझने में सहायता करता है कि आत्मनिर्भर भारत कोई तात्कालिक नारा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की दीर्घकालीन वैचारिक विरासत है।

निष्कर्ष एवं भविष्य की शोध दिशा

यदि स्वदेशी आंदोलन से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक की ऐतिहासिक यात्रा पर समग्र दृष्टि डाली जाए,

तो यह स्पष्ट होता है कि कौशल शिक्षा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक स्थायी और सशक्त विरासत रही है। गांधीजी के चरखे और खादी का संदेश केवल औपनिवेशिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आत्मनिर्भर समाज की दीर्घकालीन परिकल्पना का प्रतीक था। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत उसी ऐतिहासिक मार्ग पर पुनः अग्रसर दिखाई देता है। अंतर केवल इतना है कि अब कौशल का स्वरूप बदल चुका है— डिजिटल तकनीक, नवाचार और आधुनिक उद्योग इसके नए आयाम हैं। परंतु मूल विचार वही है— शिक्षा को उत्पादन, श्रम और आत्मनिर्भरता से जोड़ना।

भविष्य में इस विषय पर क्षेत्रीय कौशल परंपराओं, डिजिटल कौशल के ऐतिहासिक विकास तथा वैश्विक संदर्भ में भारतीय कौशल मॉडल के तुलनात्मक अध्ययन की संभावनाएँ हैं। इस प्रकार कौशल शिक्षा और आत्मनिर्भरता न केवल अतीत की विरासत हैं, बल्कि भारत के भविष्य की भी आधारशिला हैं।

संदर्भ

1. Gandhi, M. K., Hind Swaraj or Indian Home Rule, 1909.

- | | |
|---|--|
| 2. गांधी, मोहनदास करमचंद, वर्धा शिक्षा योजना, 1937. | 8. भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986. |
| 3. Tagore, Rabindranath, Swadeshi Samaj, 1904. | 9. Government of India, National Education Policy, 2020. |
| 4. Chandra, Bipan, India's Struggle for Independence, 1988. | 10. Government of India, Skill India Mission Reports, 2015 onwards. |
| 5. गुप्त, परमानंद, स्वदेशी आंदोलन का इतिहास. | 11. भारत सरकार, आत्मनिर्भर भारत अभियान, 2020. |
| 6. शर्मा, रामनारायण, गांधी और नई तालीम. | 12. शर्मा, ओम विकास, "वैज्ञानिक अनुसंधान लेखन: अभ्यास और अस्मिता", विज्ञान प्रकाश, 2022. |
| 7. भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968. | |